

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2464/2016)

10 नवंबर, 2016

[दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह, न्यायाधिपतिगण]

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 – धारा 3(1) के शुल्क की दरों की तालिका के भाग बी का स्पष्टीकरण (बी) - "खान" की परिभाषा के तहत "प्रसंस्करण" शब्द की व्याख्या - अपीलकर्ता की शिकायत "खान" की परिभाषा से संबंधित है, जिसका प्रभाव प्रसंस्करण को खनन का एक हिस्सा बनाना और "खदानो" के लिए शुल्क की उच्च दर निर्धारित करना" है। (अर्थात् खनन और प्रसंस्करण की एक समग्र गतिविधि) - का औचित्य – अभिनिर्धारित यहां "प्रसंस्करण" शब्द का अर्थ उन प्रक्रियाओं से होगा जो खनन गतिविधि से जुड़ी और जुड़ी हुई हाथों या मशीनरी की मदद से होती हैं - इसमें ऐसी प्रक्रिया शामिल नहीं होगी जिसके द्वारा एक नया या जिस वस्तु का खनन किया गया है, उसके अलावा किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है - इरादा और उद्देश्य निश्चित रूप से खदान से स्वीकार्य दूरी पर स्थापित एक विनिर्माण इकाई को उच्च दर पर बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना नहीं है - प्रासंगिक रूप से, एक विनिर्माण इकाई चाहे वह खदान से सटा हो या नहीं, कम टैरिफ का भुगतान करेगा - इस प्रकार, प्रशुल्क को विनिर्माण इकाई के लिए लगाया जाना चाहिए - बिजली प्रशुल्क - कानून की व्याख्या – मैक्सिम - नोस्किटुर ए सोसाइटी (एक अस्पष्ट या अस्पष्ट शब्द का अर्थ) - खान और खनिज।

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 - धारा 3(1) के शुल्क की दरों की तालिका के भाग बी का स्पष्टीकरण (बी) - "खान" की परिभाषा के तहत "खनिज" शब्द की व्याख्या - अपीलकर्ता की दलील है कि मैंगनीज अयस्क एक खनिज है लेकिन फेरो मैंगनीज एक खनिज नहीं है क्योंकि उक्त खनिज "मिश्र धातु" में परिवर्तित हो जाता है और खनिज नहीं रह जाता है -हालाँकि, राज्य ने तर्क दिया कि परिभाषा एक समावेशी है - अभिनिर्धारित किया : अपीलकर्ता कच्चे माल में से एक के रूप में मैंगनीज अयस्क का उपयोग कर रहा था और फेरो मैंगनीज मिश्र धातु के निर्माण के दौरान उसी का उपभोग कर रहा था - मैंगनीज अयस्क को कुचलने, उपचार करने, प्रसंस्करण आदि का चरण एकीकृत मैंगनीज लाभकारी संयंत्र (आईएमबी प्लांट) चरण में था, इसे फेरो मैंगनीज प्लांट स्तर में लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, फेरो मैंगनीज प्लांट, मैंगनीज अयस्क को कुचलने, उपचार करने, प्रसंस्करण इत्यादि में शामिल इकाई के विपरीत फेरो मैंगनीज मिश्र धातु के निर्माण में शामिल एक इकाई होने के नाते, इसे 'खदान' की विस्तारित खान की परिभाषा के भीतर नहीं माना जा सकता है- खाने और खनिज.

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. 'क्रशिंग', 'ट्रीटमेंट' और 'ट्रांसपोर्टिंग' शब्द संकीर्ण महत्व के शब्द हैं और इन शब्दों के बीच प्रयुक्त 'प्रसंस्करण' शब्द को बहुत व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि विधायी इरादा संकीर्ण है। 'प्रसंस्करण' शब्द का अर्थ सजातीय अर्थ में होगा। दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्द 'प्रसंस्करण' 'कुचलने', 'उपचार' और 'परिवहन' शब्दों द्वारा व्यक्त अर्थ तक ही सीमित होगा। आशय यह है कि खनन गतिविधियों के संबंध में देय बिजली शुल्क में खदान, खदान में या खदान के निकटवर्ती परिसर में स्थित सभी मशीनरी शामिल होगी, जिसमें खनन किए गए खनिजों को कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन

किया जाता है। यहां 'प्रसंस्करण' शब्द का अर्थ खनन गतिविधि से जुड़े हाथों या मशीनरी की मदद से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसमें वह प्रक्रिया शामिल नहीं होगी जिसके द्वारा खनन की गई वस्तु के अलावा कोई नई या भिन्न वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यह खनन और प्रसंस्करण की समग्र गतिविधि से संबंधित और उसका प्रतीक है। इरादा उन प्रक्रियाओं को शामिल करने का नहीं है जो वाणिज्यिक दुनिया में ज्ञात एक अलग वस्तु के निर्माण की ओर ले जाएंगी अन्यथा यहां तक कि विनिर्माण गतिविधि भी कवर हो जाएगी, जबकि विनिर्माण इकाई कम दर पर बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इरादा और उद्देश्य निश्चित रूप से खदान से स्वीकार्य दूरी पर स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाई को बाध्य करना नहीं है, क्योंकि खदान से सटे विनिर्माण इकाई को उच्च दर पर बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रासंगिक रूप से, किसी अन्य इकाई द्वारा स्थापित विनिर्माण इकाई, चाहे वह खदान के निकट हो या नहीं, कम प्रशुल्क का भुगतान करेगी। ऐसी बेहूदगी और अतार्किकता से बचना होगा। इसलिए, वर्तमान संदर्भ में, 'प्रसंस्करण' का अर्थ खनन किए गए खनिज को विपणन योग्य, बिक्री योग्य और परिवहन योग्य बनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों से होगा, खनन किये गये खनिज की पहचान को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना। जब खनन किए गए खनिज में पर्याप्त परिवर्तन होता है और प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक अलग वस्तु उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है और खनिज पूरी तरह से बदल जाता है, तो यह 'प्रसंस्करण' शब्द के दायरे से बाहर हो जाएगा। स्पष्टीकरण के अंत में 'खनिज' शब्द के प्रयोग को देखते हुए प्रतिबंधित निर्माण भी स्वीकार्य होगा। स्पष्टीकरण में 'खनिज' शब्द वह उत्पाद है जिसका खनन किया गया था और जिसे खनिज को 'कुचलने', 'प्रसंस्करण', 'उपचार' और 'परिवहन' के लिए रखा गया था। दूसरे शब्दों में, खनिज का अर्थ वह खनिज है जिसका खनन किया गया था, न कि खनन किए गए खनिज का

उपयोग या प्रसंस्करण करके बनाया गया कोई नया उत्पाद। [पैरा 20] [796-जी; 797-ए-जी]

रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर 1990 (2) एससीआर 797: 1990 (3) एससीसी 447; अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य 2004 (1) एससीआर 470: 2004 (1) एससीसी 755; सीआईटी बनाम तारा एजेंसी 2007 (8) एससीआर 136: 2007 (6) एससीसी 429; ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य. 2006 (8) पूरक एससीआर 790: 2006 (12) एससीसी 468; और एस्पिनवॉल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, एर्नाकुलम 2001 (2) पूरक एससीआर 559: 2001 (7) एससीसी 525- पर निर्भर।

2.1 निम्नलिखित क्रम है जिसमें खनन/प्रसंस्करण/विनिर्माण होता है: (ए) पहला चरण: अपीलकर्ता अपनी खदानों से मैंगनीज अयस्क का खनन करता है। खनन के दौरान अपीलकर्ता की बिजली की खपत पर 40% बिजली शुल्क लगाया जाता है, जिस पर अपीलकर्ता विवाद नहीं कर रहा है; (बी) दूसरा चरण: ऐसी खदानों में मैंगनीज अयस्क को अपीलकर्ता के एकीकृत मैंगनीज लाभकारी संयंत्र (आईएमबी प्लांट) में अशुद्धियों को हटाकर संसाधित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मैंगनीज सामग्री के संवर्धन के लिए अशुद्धियों और विदेशी सामग्रियों को हटाने के लिए खनिज की सफाई विभिन्न तरीकों से होती है और इस प्रक्रिया के दौरान, मैंगनीज खनिज एक खनिज बना रहता है। अपीलकर्ता द्वारा आईएमबी संयंत्र की बिजली की खपत पर 40% बिजली शुल्क लगाया जाता है, जिस पर अपीलकर्ता विवाद नहीं कर रहा है; (सी) तीसरा चरण: फेरो मैंगनीज संयंत्र में, कच्चे माल जैसे, संसाधित मैंगनीज अयस्क (जिसके लिए 40% बिजली शुल्क का भुगतान आईएमबी प्लांट द्वारा पहले ही किया जा चुका है), लौह अयस्क, कोक,

डोलोमाइट, कोयला, कार्बन, आदि, एक विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से हैं। एक पूरी तरह से नया उत्पाद जिसे व्यावसायिक रूप से फेरोमैंगनीज मिश्र धातु के रूप में जाना और बेचा जाता है, जो अलग-अलग रसायन विज्ञान के साथ और भट्ठी में गलाने के माध्यम से एक अलग उत्पाद है। [पैरा 23] [799-सी-जी]

2.2 अपीलकर्ता के फेरो मैंगनीज संयंत्र को 'मेरा' के अर्थ में लाने के लिए, राज्य ने तर्क दिया है कि फेरो मैंगनीज संयंत्र का उपयोग खनिज, यानी मैंगनीज अयस्क को "कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन के लिए" किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता न तो मैंगनीज अयस्क को कुचल रहा है, न प्रसंस्करण कर रहा है, न उपचार कर रहा है और न ही परिवहन कर रहा है, बल्कि इसे कच्चे माल में से एक के रूप में उपयोग कर रहा है और फेरोमैंगनीज मिश्र धातु के निर्माण के दौरान इसका उपभोग कर रहा है। मैंगनीज अयस्क (खनिज) को कुचलने, उपचारित करने, प्रसंस्करण आदि की स्थिति आईएमबी प्लांट (द्वितीय चरण) में थी, जहां अपीलकर्ता 40% बिजली शुल्क का भुगतान कर रहा है। वही दर फेरो मैंगनीज प्लांट (तीसरे चरण) में लागू नहीं की जा सकती क्योंकि उपरोक्त कारण से इसे 'मेरा' के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 24] [799-एच; 800-ए-सी]

2.3 यदि कोई नया पदार्थ अस्तित्व में लाया जाता है या विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाली कोई नई या अलग वस्तु विशेष प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, तो ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रियाएँ निर्माण की श्रेणी में आएंगी। [पैरा 25] [800-सी-डी]

ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता 2000 (1) एससीसी 549; एस्पिनवॉल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, एर्नाकुलम 2001 (2) पूरक एससीआर 559; 2001 (7) एससीसी 525; सर्वो-मेड

इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 2015 (6) स्केल 137
- पर भरोसा किया गया।

2.4 अपीलकर्ता द्वारा अपने फेरोमैंगनीज संयंत्र में खनिज मैंगनीज का उपयोग करके निर्मित फेरोमैंगनीज मिश्र धातु भौतिक और यहां तक कि रासायनिक रूप से खनिज कच्चे माल से पूरी तरह से अलग उत्पाद है। इसके अलावा, मैंगनीज अयस्क के विपरीत फेरोमैंगनीज मिश्र धातु कभी भी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाई जा सकती है और इसका निर्माण मैंगनीज अयस्क और अन्य खनिजों से ही किया जाना है। यही तर्क तांबे के सांद्रण पर भी लागू होता है क्योंकि एक अलग और विशिष्ट उत्पाद अस्तित्व में आता है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, दोनों मामलों में, व्यावसायिक भाषा में अलग-अलग उत्पाद सामने आए हैं। इसलिए, नोसितुर ए सोशिइस (एक अस्पष्ट या अस्पष्ट शब्द का अर्थ) के सिद्धांत को लागू करना होगा। तार्किक परिणाम के रूप में, विनिर्माण इकाई के लिए प्रशुल्क लगाया जाना चाहिये। (पैरा 30, 31) (804-ए-सी)

मप्र राज्य बनाम बिड़ला जूट एमएफजी कंपनी लिमिटेड 1995 (1) पूरक एससीआर 271: 1995 (4) एससीसी 603; हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2004 (12) एससीसी 408; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य 2004 (1) एससीआर 564: 2004 (10) एससीसी 201; यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिहार बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, पटना 1985 (19) ईएलटी 609; वी. पी. पिथुपिचाई और अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार के विशेष सचिव 2003 (3) एससीआर 1045: 2003 (9) एससीसी 534; स्टोन क्रेशर ओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम म.प्र. विद्युत मंडल एवं अन्य एमपी क्रमांक 673/1993; मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 1973 (1) एससीआर 997: 1972 (2)

एससीसी 620; ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1962 एआईआर 1733 :1963 एससीआर 404; एलेल होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1990 एआईआर 1664: 1989 (2) एससीआर 880: 1989 (3) एससीसी 698 और ए.पी. सरकार बनाम पी. लक्ष्मी देवी 2008 (3) एससीआर 330:2008 (4) एससीसी 720; तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2001 (3) एससीआर 1146: 2001 (6) एससीसी 260; भारत संघ बनाम हरजीत सिंह संधू 2001 (2) एससीआर 1127: 2001 (5) एससीसी 593 – संदर्भित किया गया।

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत – संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ

1995 (1) पूरक एससीआर 271	संदर्भित किया गया	पैरा 5
2004 (12) एससीसी 408	संदर्भित किया गया	पैरा 5
2004 (1) एससीआर 564	संदर्भित किया गया	पैरा 10
1985 (19) ईएलटी 609	संदर्भित किया गया	पैरा 10
2003 (3) एससीआर 1045	संदर्भित किया गया	पैरा 10
1973 (1) एससीआर 997	संदर्भित किया गया	पैरा 10
1963 एससीआर 404	संदर्भित किया गया	पैरा 11
1989 (2) एससीआर 880	संदर्भित किया गया	पैरा 11
2008 (3) एससीआर 330	संदर्भित किया गया	पैरा 11
2001 (3) एससीआर 1146	संदर्भित किया गया	पैरा 11

2001 (2) एससीआर 1127	संदर्भित किया गया	पैरा 11
1990 (2) एससीआर 797	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 18
2004 (1) एससीआर 470	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 18
2007 (8) एससीआर 136	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 19
2006 (8) पूरक एससीआर 790	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 19
2001 (2) पूरक एससीआर 559	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 19,26
2000 (1) एससीसी 549	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 24
2015 (6) स्केल 137	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 27

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2464/2016

रिट याचिका संख्या 9017 /2010 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रिंसिपल सीट जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 01.12.2011 से

साथ

सी.ए. संख्या 2465-2467/2016,

मुकुल रोहतगी, एजी, पी. पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. जी नारायणन नायर, देवाशीष भारुका, के. एन. मधुसूदनन, रवि भारुका, आर. के. सांघी, सुश्री नंदिनी सेन, देबा प्रसाद मुखर्जी, अधिवक्तागण; अपीलकर्ता के लिए।

अमलपुष्प श्रोती, बी.एस. बांठिया, मिश्रा सौरभ, अमित कुमार लाल, अधिवक्तागण; प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलों के इस बैच में, विशेष अनुमति द्वारा, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 9017/2010 में पारित दिनांक 1.12.11, के अलग-अलग आदेशों की कानूनी स्थिरता पर हमला किया गया, जो मैंगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड और एमपीएन द्वारा दायर रिट याचिका से संबंधित है। और एम.पी. नं. 2821/1988, एम.पी.नं; 3827/1993 एवं डब्ल्यू.पी.नं. 3103/1994, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।

2. चूंकि विवाद की समानता मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (संक्षिप्तता के लिए, "अधिनियम") के भाग-बी के स्पष्टीकरण (बी) के तहत परिभाषित "खदान" की परिभाषा के तहत "खनिज" और "प्रसंस्करण" शब्दों की व्याख्या के आसपास केंद्रित है, हम अधिनियम की योजना और होने वाले विभिन्न मुकदमों की गणना करेंगे और उसके बाद प्रत्येक मामले में तथ्यों का उल्लेख करेंगे। संक्षिप्तता के लिए और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, हमने शुरुआत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मामले में मुकदमेबाजी और पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया है।

3. तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार विधान सभा ने सीपी और बरार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 अधिनियमित किया था जिसे मध्य प्रदेश राज्य में अपनाया गया था और इसे मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के रूप में जाना जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित अधिनियम में प्रावधान है कि यह विद्युत ऊर्जा की बिक्री या खपत पर शुल्क लगाने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम की धारा 3(1) तदनुसार विद्युत ऊर्जा की बिक्री या खपत पर शुल्क लगाने का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि धारा 3-ए में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन, विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक वितरक और प्रत्येक उत्पादक को राज्य सरकार को हर महीने निर्धारित समय पर और निर्धारित तरीके से नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट दरों पर गणना शुल्क का भुगतान करना होगा।

पिछले महीने के दौरान किसी उपभोक्ता को बेची या आपूर्ति की गई या उसके स्वयं के प्रयोजनों के लिए या उसकी टाउनशिप या कॉलोनी के प्रयोजनों के लिए उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाइयों पर। धारा 3(1) की तालिका उस उद्देश्य के आधार पर शुल्क की विभिन्न दरें निर्धारित करती है जिसके लिए विद्युत ऊर्जा बेची जाती है। तालिका का भाग-बी उसके उद्देश्यों के लिए बेची, आपूर्ति या खपत की गई विद्युत ऊर्जा के लिए शुल्क की विभिन्न दरों का प्रावधान करता है। उक्त तालिका का आइटम 3 इस प्रकार है:-

"3. खदानें (सीमेंट उद्योग की कैप्टिव 40 खदान के अलावा)

4. अंक 40 'प्रति यूनिट बिजली शुल्क के प्रतिशत के रूप में शुल्क की दर' शीर्षक के अंतर्गत आता है। धारा 3(1) का स्पष्टीकरण (बी) "खान" को इस प्रकार परिभाषित करता है: -

"स्पष्टीकरण.- (बी) "खान" का अर्थ है एक खदान जिस पर खान अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 35) लागू होता है और इसमें खदान में या उसके निकट स्थित परिसर या मशीनरी शामिल है और जिसका उपयोग कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार या खनिज के परिवहन के लिए किया जाता है।"

5. यहां यह बताना आवश्यक है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने धारा 3 और तालिका भाग-बी आइटम 4 (जो 1995 के संशोधन के बाद अब आइटम नंबर 3 है) और स्पष्टीकरण (बी) के प्रावधान को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी। जिसमें संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर खानों की विस्तारित परिभाषा शामिल है। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलेगा, उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम बिड़ला जूट एमएफजी कंपनी लिमिटेड' पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। मामला इस न्यायालय तक पहुंचा, जो अंततः सिविल अपील संख्या 3248-50 /

1998 का विषय बना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुये राय दी कि मुख्य विवाद जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी, वह यह था कि स्पष्टीकरण के खंड (बी) में मद संख्या 4 के अंतर्गत की धारा 3 में निहित तालिका में "खान" शब्द को कैसे समझा जाए। इस न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलीलों पर ध्यान दिया कि उसके द्वारा की गई गतिविधियाँ "आसन्न" क्षेत्र शब्द के अर्थ में नहीं आती हैं और इसके अलावा उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण चयनात्मक और भेदभावपूर्ण था। चूंकि उठाए गए निवेदनों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया, लेकिन उसने अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई गतिविधियों के संबंध में या कैसे के संदर्भ में अधिक विस्तार से तथ्यों की जांच किए बिना मामले का निपटारा कर दिया। मामले के तथ्यों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, "आसन्न" शब्द का अर्थ समझा जाना चाहिए, न्यायालय ने यह कहते हुए रिट याचिका को उच्च न्यायालय में भेज दिया: -

"इन परिस्थितियों में, हम इसे उचित और उचित मानते हैं कि उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों और विवाद से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उचित सम्मान रखते हुए, पक्षों की ओर से आगे बढ़ाए गए तर्कों की नए सिरे से जांच करनी चाहिए। चूंकि हम मामले को उच्च न्यायालय में भेजने का विचार कर रहे हैं, इसलिए हम पक्षकारों द्वारा आग्रह किए गए संबंधित विवादों के गुण-दोष के आधार पर एक या दूसरे तरीके से व्यक्त नहीं करना चाहते हैं...।"

6. छूट के बाद, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सिविल अपील संख्या 6725 /2008 में विशेष अनुमति द्वारा अपील में खारिज कर दिया गया था। दूसरे दौर में, दो-न्यायाधीशों

की पीठ ने उन तथ्यों को विस्तार से बताया जो इस आशय के हैं कि इसमें अपीलकर्ता ओपन कास्ट खनन प्रक्रिया द्वारा तांबे के अयस्क के निष्कर्षण में लगा हुआ है, जिसमें खुले गड्ढे वाली खदान में अयस्क को ड्रिलिंग और ब्लास्ट करना शामिल है, बोल्टर के रूप में अयस्क को प्राथमिक क्रशर (खदान से 2.53 किमी की दूरी पर स्थित) तक पहुंचाया जाता है जहां इसे कंकड़/टुकड़ों में कुचल दिया जाता है और ऐसे कुचले हुए अयस्क को फिर छोटे कंकड़ में कुचलने के लिए एक कन्वेयर पर एक सेकेंडरी क्रशर (खदान से लगभग 5 किमी दूर स्थित) में ले जाया जाता है। उक्त चरण के बाद, छोटे टुकड़ों/कंकड़ों को एक कन्वेयर द्वारा कंसन्ट्रेटर प्लांट (खदान से 5.5 किमी पर स्थित) तक ले जाया जाता है।

7. यह न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को बताने के लिए आगे बढ़ा। यह दावा किया गया था कि:-

"4. सांद्रक संयंत्र में, अयस्क को बॉल मिलों में पीसकर पाउडर बनाया जाता है। पानी के साथ मिश्रित ऐसे पाउडर को घोल के रूप में फ्लोटेशन कोशिकाओं में ले जाया जाता है। फ्लोटेशन कोशिकाओं में, घोल को झाग फ्लोटेशन प्रक्रिया के अधीन किया जाता है और तांबे के सांद्रण को हटा दिया जाता है और वैक्यूम ड्रायर में सुखाया जाता है और सांद्रण भंडारण शेड में संग्रहित किया जाता है। टेलिंग पंप 8 किमी की दूरी पर हैं। मिलिंग में उपयोग के लिए सांद्रक संयंत्र के लिए बड़ी मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। फैक्ट्री टाउनशिप के लिये भी पानी की आवश्यकता होती है। आवश्यक पानी को खदानों से एक इनटेक वेल (खदान से 10 किमी की दूरी पर स्थित) पर स्थित पंपों के माध्यम से पंप किया जाता है। इनटेक वेल से, पानी को जल उपचार संयंत्र (खदान से 6 किमी. की दूरी पर स्थित) में पंप किया जाता है।

5. अपीलकर्ता के अनुसार, इसकी गतिविधियों में दो अलग-अलग भाग शामिल हैं। सबसे पहले खनन है, यानी ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और अयस्क का संग्रह जो खदान के गड्ढे में किया जाता है। यह गतिविधि खान अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत खदान क्षेत्र में की जाती है। दूसरा प्रसंस्करण है, जो प्राथमिक क्रशर, द्वितीयक क्रशर और कंसन्ट्रेटर प्लांट पर किया जाता है। गतिविधियों का प्रसंस्करण (विनिर्माण) भाग कारखाना क्षेत्र में किया जाता है। प्राथमिक क्रशर, द्वितीयक क्रशर, बॉल मिल, कंसन्ट्रेटर प्लांट, टेलिंग पंप, इनटेक वेल और जल उपचार संयंत्र खदान से दूर 2.5 किमी से 10 किमी की दूरी पर स्थित हैं और फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत एक "फ़ैक्ट्री" के रूप में अलग से पंजीकृत हैं। खुले गड्ढे वाली खदान (खनन क्षेत्र) और प्रसंस्करण संयंत्र/मशीनरी (कारखाना क्षेत्र) सभी राज्य सरकार से खनन पट्टे पर ली गई भूमि के एक बड़े हिस्से में स्थित हैं।"

8. दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले के कालक्रम पर ध्यान दिया और कहा कि अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत "खान" की परिभाषा से संबंधित है, जिसका प्रभाव प्रसंस्करण को खनन का एक हिस्सा बनाना और उच्चतर के नुस्खे से है। "खानों" (जो खनन और प्रसंस्करण की समग्र गतिविधि है) के लिए शुल्क की दर, जबकि उद्योगों की अन्य श्रेणियों के लिए कम दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कारखानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (ए) वे जो खदान से सटे हैं और खनिज को कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार और परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं; और (बी) अन्य कारखानों की अनुमति है। अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया था कि "खदानों से सटे" शब्द अस्पष्ट और अस्पष्ट है जो प्राधिकारी के भेदभावपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाता है। इसके अलावा, इसका प्रसंस्करण संयंत्र, यानी प्राथमिक क्रशर, सेकेंडरी क्रशर, बॉल मिल, कंसन्ट्रेटर प्लांट, टेलिंग पंप, इनटेक वेल और

जल उपचार संयंत्र इसकी खदान के "निकट" में स्थित नहीं हैं और इसलिए ऐसा नहीं हो सका। विद्युत शुल्क लगाने के उद्देश्य से इसे "खान" माना जाएगा। न्यायालय ने पिछले अवसर पर छूट के आदेश के बाद उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दों पर भी ध्यान दिया। उक्त मुद्दे इस प्रकार हैं:-

"(i) क्या एक खदान ('खान' की विस्तारित परिभाषा के अंतर्गत आने वाली 'फैक्ट्री') और अन्य कारखानों से सटे प्रसंस्करण संयंत्र और मशीनरी के लिए कर की अलग-अलग दरें निर्धारित करना भेदभावपूर्ण और मनमाना है और इसलिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है?

(ii) क्या अधिनियम की धारा 3 के तहत तालिका में स्पष्टीकरण (बी) में 'खान' शब्द की परिभाषा, अधिनियम के तहत प्राधिकरण को यह तय करने के लिए अनियंत्रित विवेक देती है कि 'खदान से सटे' क्या है और इसलिए अमान्य है?

(iii) क्या किसी खदान से सटे शब्दों का उपयोग केवल खदान से सटे या उससे सटे अयस्कों या मशीनरी से होगा, न कि लगभग 2.5 से 6 किमी की दूरी पर स्थित परिसर या संयंत्र/मशीनरी?

(iv) क्या राज्य ने याचिकाकर्ता से शुल्क वसूलने और भिलाई स्टील, बाल्को, मैंगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड से शुल्क वसूलने में अलग-अलग मानदंड लागू किए थे और इस तरह भेदभाव किया था?"

9. यहां यह बताना जरूरी है कि अपीलकर्ता द्वारा एक तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने वास्तविक मुद्दों पर विचार नहीं किया था और निर्धारण के लिए तैयार किए गए प्रश्नों में वास्तविक मुद्दों और विवादों को शामिल नहीं किया गया था। न्यायालय ने विवाद को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया:-

"21. अधिनियम को म.प्र. विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में "संशोधन अधिनियम") द्वारा संशोधित किया गया था। भाग बी में शुल्क की विभिन्न दरें प्रदान की गई हैं। उक्त भाग में, खंड (4) सीमेंट कारखाने की कैप्टिव खदानों के अलावा अन्य खदानें और दर 50 पैसे प्रति यूनिट ऊर्जा से संबंधित है। स्पष्टीकरण (बी) "खान" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"(बी) 'खदान' का अर्थ एक ऐसी खदान है जिस पर खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) लागू होता है और इसमें खदान में या उसके निकट स्थित परिसर या मशीनरी शामिल है और जिसका उपयोग खनिज को कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन के लिए किया जाता है।"

22. यह प्रस्तुत किया गया कि खानों से संबंधित प्रविष्टि खनिज के प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन को संदर्भित करती है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार जोर "खनिज" अभिव्यक्ति पर है। यह इंगित किया गया था कि अपीलकर्ता "काँपर कंसन्ट्रेट" का निर्माण कर रहा है, जो एक खनिज नहीं है और यह "खनन" नहीं कर रहा है, जहां तक कि यह उपरोक्त श्रेणियों के तहत कवर नहीं किए गए अन्य उद्योगों के लिए खंड (7) के अंतर्गत आता है, जहां दर है 5 पैसे प्रति यूनिट ऊर्जा। मूलतः निवेदन यह है कि स्पष्टीकरण केवल खनन या खनिजों से संबंधित है। जो उत्पाद शुल्क योग्य है वह "काँपर कंसन्ट्रेट" है क्योंकि विनिर्माण की एक प्रक्रिया शामिल होती है। यह देखा गया है कि निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए बिंदु (ii) और (iv) वास्तव में प्रासंगिक हैं। लेकिन विवाद के वास्तविक सार को कवर करने के लिए बिंदुओं को सही ढंग से तैयार नहीं किया गया है। सही प्रश्न इस प्रकार होगा:

"क्या तांबा सांद्रण एक खनिज है और क्या अधिनियम के भाग बी का स्पष्टीकरण लागू होता है, भले ही इसे अस्तित्व में लाने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया शामिल हो?"

पूर्वोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया और पक्षों को अपने-अपने रुख के समर्थन में सामग्री रखने की अनुमति देने के लिए तैयार किए गए प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया।

10. रिमांड के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि खनिज एक ऐसी चीज है जो खदान में उगती है और इसे बेहतर या कीमती उपयोग के लिए प्राप्त या निकाले जाने में सक्षम है। आगे यह तर्क दिया गया कि तांबे के अयस्क को खदान के गड्ढे से निकाला जाता है और फिर इसे प्रसंस्करण के अधीन किया जाता है जिसके बाद तांबा अयस्क तांबे के सांद्रण में बदल जाता है जो एक अलग वस्तु है जो एक उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद है। उस आधार पर, यह आग्रह किया गया कि तांबा सांद्रण "खनिज" नहीं है और परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 3 के भाग-बी का स्पष्टीकरण (बी) लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य और यूरैनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिहार बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, पटना पर भरोसा रखा गया। राज्य की ओर से, यह आग्रह किया गया था कि तांबा सांद्रण एक "खनिज" है, जो खान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में, "1952 अधिनियम") के साथ-साथ अनुसूचियों की धारा 2(आईजे) में निहित परिभाषा के संबंध में है। I और II को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में जोड़ा गया। खंडपीठ को वी.पी. पिथुपिचाई और अन्य बनाम टी.एल. सरकार के विशेष सचिव में प्राधिकरण की सराहना की गई एवं स्टोन क्रेशर ओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम म.प्र. विद्युत बोर्ड एवं अन्य में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय को अनुमोदिन किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से सक्षम प्राधिकारी म.प्र. बिजली बोर्ड ने तर्क दिया कि तांबा अयस्क केवल इसलिए "खनिज" नहीं रह जाता है क्योंकि यह कथित प्रसंस्करण के अधीन है और इसलिए तांबा सांद्रण एक खनिज के रूप में अपनी पहचान नहीं खोता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही तांबे के अयस्क को प्रसंस्करण के अधीन किया जाता है, फिर भी मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में निर्णय पर निर्भरता रखने से इसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है।

11. उच्च न्यायालय ने बार में प्रतिद्वंद्वितापूर्ण दलीलों पर विचार करते हुए यह माना कि राज्य के पास कराधान के लिए जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि दरों को चुनने और चुनने का अधिकार है यदि वह उचित रूप से ऐसा करता है और उक्त उद्देश्य के लिए ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य पर निर्भरता रखता है। इसने आगे कहा कि कराधान के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं, व्यक्तियों और चीजों के वर्गीकरण के मामलों में विधायिका के पास अक्षांश उपलब्ध है और इसे कराधान नीति के निर्माण में शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखना होगा। उक्त राय व्यक्त करने के लिए, उच्च न्यायालय ने एलेल होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' और ए.पी. सरकार बनाम पी. लक्ष्मी डेविल पर भरोसा जताया। इसके बाद इसने विषय-और-वस्तु नियम का उल्लेख किया और उस संबंध में वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया और तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य और भारत संघ बनाम हरजीत सिंह संधू" के मामले में प्रकरण इसकी सराहना की। उपरोक्त तरीके से कानूनी प्रस्ताव बताने के बाद, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1949 अधिनियम एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य विद्युत ऊर्जा की बिक्री या खपत पर शुल्क लगाने का प्रावधान करना है और अधिनियम ने भारत सरकार

अधिनियम, 1953 की सूची II के आइटम 48 (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 53, अर्थात् बिजली की खपत या बिक्री पर कर से मेल खाती है। इसने अधिनियम की धारा 3 और 'खान' शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम के तहत बिजली शुल्क एक कर है जो बिजली की खपत की बिक्री पर लगाया जाता है और आगे कहा गया है कि यदि तालिका अधिनियम की धारा 3 से जुड़ी है, विद्युत शुल्क लगाने के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण उस उद्देश्य पर आधारित है जिसके लिए विद्युत ऊर्जा बेची या खपत की जाती है और शुल्क लगाने के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण तालिका है। वर्गीकरण के पहलू से निपटते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि:-

" अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ स्पष्ट संबंध है, अर्थात्, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को समूहीकृत करके राजस्व बढ़ाना और उद्योग की प्रकृति के आधार पर शुल्क की विभिन्न दरें निर्धारित करना। खनन उद्योग के लिए बिजली शुल्क की उच्चतम दर विधायिका द्वारा अपने विवेक से निर्धारित की जाती है। विद्युत शुल्क की उच्चतम दर निर्धारित करने का उद्देश्य गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा का दोहन करने वाले व्यक्ति/उद्योग पर कर लगाना प्रतीत होता है। शोषक को अधिक योगदान करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के योगदान का उपयोग, उम्मीद है, उन लोगों के कल्याण के लिए किया जा सके जिनके पास ऐसी प्राकृतिक संपदा है।

12. इतना कहने के बाद, यह 'खान' शब्द की परिभाषा की शारीरिक रचना पर ध्यान दिया गया और देखा गया कि अभिव्यक्ति एक कानूनी कल्पना बनाती है और इसलिए, परिभाषा में केवल वही शामिल होगा जो 'खान' भाग के सामान्य अर्थ में शामिल है, साथ

में परिभाषा के समावेशी भाग में जो उल्लेख किया गया है और इसलिए, वैधानिक व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के अनुसार अधिनियम के विषय और उद्देश्य के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य शुल्क की दर निर्धारित करके राजस्व बढ़ाना है और शुल्क की उच्चतम दर खनन उद्योगों के लिए निर्धारित है क्योंकि यह प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहा है जो गैर-नवीकरणीय है, इसलिए, इसे अधिक भुगतान करना होगा शुल्क की दर जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने कहा:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिव्यक्ति 'खान' एक कानूनी कल्पना पैदा करती है और यदि 'खनिज' शब्द को अधिनियम के संदर्भ और वस्तु के अधीन पढ़ा जाता है, तो यह ग्राफिक रूप से स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति 'खनिज' को व्यापक अर्थ दिया जाना है। यदि तांबे के अयस्क को प्रसंस्करण द्वारा तांबे के सांद्रण में परिवर्तित किया जाता है, तो यह केवल तांबे के सांद्रण में तांबे की मात्रा को समृद्ध करता है और तांबे से तांबे के सांद्रण में परिवर्तित होने पर यह 'खनिज' नहीं रह जाता है।

पूर्ववर्ती विश्लेषण के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय में तांबे का सांद्रण एक खनिज है जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के भाग बी के स्पष्टीकरण (बी) में परिभाषित किया गया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 3 के भाग बी के स्पष्टीकरण (बी) में उस पर लागू होता है।

इसके अलावा "तांबा सांद्रण: अंतिम उत्पाद है। कुचला हुआ, संसाधित, उपचारित या परिवहन किया गया" क्या है, तांबा सांद्र नहीं बल्कि अयस्क है। प्रश्न में बिजली का उपयोग ऐसे "क्रशिंग, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन" के लिए किया जा रहा है।

13. "आसन्न" शब्द पर ध्यान देना और खदान के नजदीक स्थित उद्योगों और समान गतिविधि करने वाले अन्य उद्योगों, अर्थात् 'क्रशिंग, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन', जो स्थित नहीं हैं, के बीच भेदभाव से संबंधित तर्क उठाया गया है। खदान के इतने करीब होने पर, खंडपीठ ने कहा कि:-

"आसन्न" शब्द का अर्थ 'सटा हुआ' या 'सटा हुआ' नहीं है, लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ है, और इसमें एक ही इलाके में निकटता भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव विवादित नहीं है, और इसलिए, इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है मामले के कानून में 'आसन्न' शब्द के अर्थ का हवाला दिया गया है। जवाब में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि यह भेदभाव उचित है क्योंकि परिवहन लागत जैसे बढ़े हुए ओवरहेड्स को दूर के उद्योगों को उच्च कर के अधीन नहीं करने के लिए माना गया है।

14. जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, तो मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी और श्री पी.पी. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील राव ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने 1949 अधिनियम की धारा 3(1) के स्पष्टीकरण (बी) के तहत दी गई परिभाषा के आधार पर बिजली शुल्क लगाकर गंभीर गलती की है। श्री रोहतगी द्वारा यह तर्क दिया गया कि मैंगनीज अयस्क खान अधिनियम, 1952 के तहत एक खनिज है, लेकिन फेरो मैंगनीज एक खनिज नहीं है क्योंकि उक्त खनिज "मिश्र धातु" में परिवर्तित हो जाता है और खनिज नहीं रह जाता है। श्री पी.पी. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि तांबा एक खनिज है, लेकिन तांबे के सांद्रण में खनिज का कोई गुण नहीं होता है और इसलिए, शुल्क 8% की दर से लगाया जाना चाहिए, न कि 40% की दर से।

15. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील श्री सौरभ ने तर्क दिया कि परिभाषा एक समावेशी है और इसलिए, जब खनिज को मिश्र धातु में परिवर्तित करने के उद्देश्य से संसाधित किया जाता है, तो 40% की दर से शुल्क लगाया जाता है। राज्य के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण बिल्कुल बचाव योग्य है।

16. मामले का जोर यह है कि क्या खनिज यानी अयस्क के खनन के बाद की उपरोक्त गतिविधि को आइटम 3(1) के स्पष्टीकरण बी में प्रयुक्त 'प्रसंस्करण' शब्द द्वारा कवर किया जाएगा जो 'खान' शब्द को परिभाषित करता है। उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार खदान का अर्थ वह खदान है जिस पर खान अधिनियम, 1952 लागू होता है। खान अधिनियम, 1952 में परिभाषित "खान" शब्द इस प्रकार है:-

"(i) "खदान" का अर्थ है कोई भी उत्खनन जहां खनिजों की खोज या प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई ऑपरेशन किया गया है, और इसमें शामिल है

(i-iv)....

(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खदान में लाने या निकालने या वहां से कचरा हटाने के लिए प्रदान किए गए सभी कन्वेयर या हवाई रोपवे;

(vi) किसी खदान में या उससे सटे और उससे संबंधित सभी संपादन, स्तर, मशीनरी, रेलवे, ट्रामवे और साइडिंग;

(vii) खदान में या उसके आस-पास किए जा रहे सभी सुरक्षात्मक कार्य;"

17. खान अधिनियम, 1952 में परिभाषित 'खनिज' शब्द इस प्रकार है:

"(jj) "खनिज" का अर्थ है वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी से खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, उत्खनन या किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें खनिज तेल (जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं) शामिल हैं।

18. खनन में हर उस गतिविधि को शामिल किया जाएगा जिसके द्वारा पृथ्वी से खनिज निकाला या प्राप्त किया जाता है, भले ही ऐसी गतिविधि सतह पर या आंत में की जाती है, लेकिन यह खनिज प्राप्त करने के लिए एक गतिविधि होनी चाहिए। आइटम 3 'खदान' के प्रयोजन के लिए जिसमें विद्युत ऊर्जा बेची, आपूर्ति या खपत की जाती है, इसमें खदान के निकट स्थित मशीनरी या परिसर शामिल होंगे, बशर्ते बिजली का उपयोग खनिजों को कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन के लिए किया जाता है। अधिनियम के तहत उपरोक्त स्पष्टीकरण में प्रयुक्त 'खनिज' शब्द का संदर्भ उस खनिज से होगा जिसका खनन किया जाता है और फिर कुचला जाता है, संसाधित किया जाता है, उपचारित किया जाता है या परिवहन किया जाता है। स्पष्टीकरण में प्रयुक्त 'प्रसंस्करण' शब्द की व्याख्या संदर्भ में और उक्त वस्तु के उद्देश्य के लिये की जानी चाहिए। प्रक्रिया को व्यापक या संकीर्ण अर्थ दिया जा सकता है। जिस संदर्भ में इसका उपयोग स्पष्टीकरण में किया गया है, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि इसे एक अर्थ दिया जाना चाहिए जो तब उभरता है जब हम नोसितुर ए सोशियस के नियम को लागू करते हैं जिसका अर्थ है कि शब्द का अर्थ कंपनी द्वारा तय किया जाना है, यह रखता है। [देखें: रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर]। नोस्किटुर ए सोसिश का नियम अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य में लागू और स्वीकार किया गया है। 'क्रशिंग' और 'ट्रीटमेंट' से जुड़े

शब्दों के साथ व्याख्या और समझ की जानी चाहिए। 'प्रोसेसिंग' शब्द पहले और बाद में प्रयुक्त 'क्रशिंग' और 'ट्रीटमेंट' शब्द को ध्यान में रखते हुए अर्थ के प्रति ग्रहणशील है।

19. हम इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि जब भाषा स्पष्ट हो और कोई अस्पष्टता न हो, तो कोई सामाजिक नियम लागू नहीं होता है, जो हमारे अनुसार मौजूद है और प्रश्न में स्पष्टीकरण में बोधगम्य है। यदि 'प्रसंस्करण' शब्द की एक बहुत व्यापक और व्यापक परिभाषा लागू की जाए तो इसमें एक नए या विशिष्ट उत्पाद का निर्माण शामिल होगा। निर्माण में आम तौर पर हाथ या मशीन द्वारा प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। यदि प्रतिबंधित निर्माण लागू नहीं किया जाता है तो यह अस्वीकार्य परिणाम पैदा करेगा और जन्म देगा। विनिर्माण गतिविधियों को प्रसंस्करण के रूप में मानने और मानने का इरादा नहीं है। जैसा कि समझा जाता है, विनिर्माण का अर्थ विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें कच्चे माल को विभिन्न परिचालनों द्वारा परिवर्तन के अधीन किया जाता है। [प्रक्रिया और विनिर्माण के बीच अंतर के लिए सीआईटी बनाम तारा एजेंसी, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और एस्पिनवॉल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, एर्नाकुलम" देखें।]

20. 'क्रशिंग', 'ट्रीटमेंट' और 'ट्रांसपोर्टिंग' शब्द संकीर्ण महत्व के शब्द हैं और इन शब्दों के बीच प्रयुक्त 'प्रसंस्करण' शब्द को बहुत व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि विधायी मंशा, हमारे अनुसार, संकीर्ण है। 'प्रसंस्करण' शब्द अपना अर्थ ठोस अर्थ में लेगा। दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्द 'प्रसंस्करण' 'कुचलने', 'उपचार' और 'परिवहन' शब्दों द्वारा व्यक्त अर्थ तक ही सीमित रहेगा। आशय यह है कि खनन गतिविधियों के संबंध में देय बिजली शुल्क में खदान, खदान में या माइक के निकट के परिसर में स्थित सभी मशीनरी शामिल होगी, जिसमें खनन किए गए खनिजों की क्रशिंग, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन किया जाता है। यहां 'प्रसंस्करण' शब्द का अर्थ खनन गतिविधि से जुड़े हाथों

या मशीनरी की मदद से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसमें वह प्रक्रिया शामिल नहीं होगी जिसके द्वारा खनन की गई वस्तु के अलावा कोई नई या भिन्न वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यह खनन और प्रसंस्करण की समग्र गतिविधि से संबंधित और उसका प्रतीक है। इरादा उन प्रक्रियाओं को शामिल करने का नहीं है जो वाणिज्यिक दुनिया में ज्ञात एक अलग वस्तु के निर्माण की ओर ले जाएंगी अन्यथा यहां तक कि विनिर्माण गतिविधि भी कवर हो जाएगी, जबकि विनिर्माण इकाई कम दर पर बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इरादा और उद्देश्य निश्चित रूप से खदान से स्वीकार्य दूरी पर स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाई को बाध्य करना नहीं है, क्योंकि खदान से सटे विनिर्माण इकाई को उच्च दर पर बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रासंगिक रूप से, किसी अन्य इकाई द्वारा स्थापित विनिर्माण इकाई, चाहे वह खदान के निकट हो या नहीं, कम टैरिफ का भुगतान करेगी। ऐसी बेहदगी और अतार्किकता से बचना होगा। इसलिए, वर्तमान संदर्भ में, हम मानते हैं कि 'प्रसंस्करण' का अर्थ खनन किए गए खनिज की पहचान को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना, खनन किए गए खनिज को विपणन योग्य, बिक्री योग्य और परिवहन योग्य बनाने के लिए गतिविधियां करना होगा। जब खनन किए गए खनिज में पर्याप्त परिवर्तन होता है और प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक अलग वस्तु उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है और खनिज पूरी तरह से बदल जाता है, तो यह 'प्रसंस्करण' शब्द के दायरे से बाहर हो जाएगा। स्पष्टीकरण के अंत में 'खनिज' शब्द के प्रयोग को देखते हुए प्रतिबंधित निर्माण भी स्वीकार्य होगा। स्पष्टीकरण में 'खनिज' शब्द वह उत्पाद है जिसका खनन किया गया था और जिसे खनिज को 'कुचलने', 'प्रसंस्करण', 'उपचार' और 'परिवहन' के लिए रखा गया था। दूसरे शब्दों में, खनिज का अर्थ वह खनिज है जिसका खनन किया गया था, न कि खनन किए गए खनिज का उपयोग या प्रसंस्करण करके बनाया गया कोई नया उत्पाद।

21. ध्यान दें, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील यह प्रस्तुत किया कि पृथ्वी में उपलब्ध धातुएं और खनिज शायद ही कभी शुद्ध रूप और शुद्धता की डिग्री में पाए जाते हैं जो अंतिम उपयोगकर्ता मांग करते हैं। वे भौतिक या रासायनिक रूप से और अक्सर दोनों, अन्य पदार्थों के साथ घनिष्ठ रूप से मिश्रित होते हैं। उपयोग के लिए अच्छे को बेकार पदार्थों से अलग करना होगा। मूलतः भौतिक तरीकों से अयस्कों के बेकार अंशों को अलग करने और त्यागने के लिए किए जाने वाले उपचारों का कुल योग "अयस्क ड्रेसिंग" कहलाता है। अयस्क ड्रेसिंग के विभिन्न तरीकों में हाथ से चुनना, छंटाई, स्क्रीनिंग, धुलाई, जिगिंग, चुंबकीय पृथक्करण, कुचलना, पीसना आदि शामिल हैं। इस प्रक्रिया में, प्रसंस्करण/ड्रेसिंग से पहले और बाद में खनन किए गए खनिज की रासायनिक संरचना और गुणों में इसे बिक्री योग्य बनाने के लिए कोई बदलाव नहीं होता है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि खनिज/ड्रेसिंग खनिज प्रसंस्करण का विषय है।

22. जैसा कि ऊपर बताया गया है, मिश्र धातु आदि का निर्माण धातुकर्म का विषय है और इंजीनियरिंग की धातुकर्म शाखा का एक हिस्सा है। अयस्क ड्रेसिंग को ऐसे तरीकों से विपणन योग्य खनिज प्राप्त करने के लिए कच्चे खनिज के प्रसंस्करण के रूप में परिभाषित किया गया है जो खनिजों की रासायनिक पहचान को नष्ट नहीं करता है। दूसरी ओर, फेरो मैंगनीज मिश्र धातु जैसा मिश्र धातु एक निर्माण विधि का परिणाम है जिसमें अपीलकर्ता के मामले में इलेक्ट्रोथर्मिक गलाना शामिल होता है जो अंततः मैंगनीज अयस्क की रासायनिक पहचान को बदल देता है जिसके परिणामस्वरूप फेरो मैंगनीज मिश्र धातु बनता है। इस विधि में फेरो मैंगनीज मिश्र धातु के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता होती है। फेरो मिश्र धातु को लोहे के एक मिश्र धातु के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कुछ तत्व या तत्व जैसे मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम या वैनेडियम की पर्याप्त मात्रा होती है जो इन तत्वों

को लोहे और स्टील में पेश करने का साधन है। परंपरागत रूप से, फेरो मिश्र धातुओं की पहचान या पदनाम उनमें मौजूद प्रमुख आधार धातुओं द्वारा किया जाता है। फेरो मिश्र धातुओं के नाम रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करके संक्षिप्त किए गए हैं, उदाहरण के लिए, FeMn, FeSi और FeCr, जो क्रमशः फेरो मँगनीज, फेरो सिलिकॉन और फेरो क्रोमियम के लिए हैं। फेरो मँगनीज मिश्र धातु के निर्माण में कच्चे माल के रूप में मँगनीज अयस्क का उपयोग शामिल होता है जिसे अन्य कच्चे माल (डोलोमाइट, लौह अयस्क, कोक, कोयला और कार्बन पेस्ट) के साथ इलेक्ट्रोथर्मिक गलाने के अधीन किया जाता है। इलेक्ट्रोथर्मिक स्मेल्टिंग द्वारा फेरो मँगनीज का निर्माण चार्ज में गहराई तक डूबे हुए इलेक्ट्रोड के साथ एक निरंतर गलाने की प्रक्रिया है। गलाने में निम्नलिखित चरण शामिल हैं: सामग्री को पूर्व-हीटिंग करना, सुखाना और वाष्पशील पदार्थों को हटाना, ऑक्साइड को कम करना, और धातु और स्लैग को गलाना। तांबे का सांद्रण, एक नया और अलग वाणिज्यिक उत्पाद बनाने के लिए समान तर्क और विनिर्माण प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। यह वह खनिज नहीं है जिसका खनन किया गया है।

23. यह आग्रह किया जाता है कि फेरोमँगनीज एक मिश्रधातु है और खनिज नहीं है। यह मँगनीज और लोहे का एक मिश्र धातु है और प्राकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं है। इसका निर्माण अपीलकर्ता-मँगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड के फेरोमँगनीज संयंत्र में मँगनीज अयस्क, लोहा, कोयला, कोक, डोलोमाइट आदि जैसे कच्चे माल का उपयोग करके किया जाता है। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता, मँगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड के पास है। इसका मँगनीज अयस्क खदान क्षेत्र, एक एकीकृत मँगनीज लाभकारी संयंत्र (आईएमबी प्लांट) और एक फेरो मँगनीज प्लांट (एफएमपी) भी है। निम्नलिखित क्रम है जिसमें खनन/प्रसंस्करण/विनिर्माण होता है:-

ए. पहला चरण: अपीलकर्ता अपनी खदानों से मैंगनीज अयस्क का खनन करता है। खनन के दौरान अपीलकर्ता की बिजली की खपत पर 40% बिजली शुल्क लगाया जाता है, जिस पर अपीलकर्ता विवाद नहीं कर रहा है।

बी. दूसरा राज्य: ऐसी खदानों में मैंगनीज अयस्क को अपीलकर्ता के एकीकृत मैंगनीज लाभकारी संयंत्र (आईएमबी प्लांट) में अशुद्धियों को हटाकर संसाधित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मैंगनीज सामग्री के संवर्धन के लिए अशुद्धियों और विदेशी सामग्रियों को हटाने के लिए खनिज की सफाई विभिन्न तरीकों से होती है और इस प्रक्रिया के दौरान, मैंगनीज खनिज एक खनिज बना रहता है। अपीलकर्ता द्वारा आईएमबी प्लांट की बिजली की खपत पर 40% बिजली शुल्क लगाया जाता है, जिस पर अपीलकर्ता विवाद नहीं कर रहा है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि ऐसे संसाधित मैंगनीज अयस्क का 95% से 98% खुले बाजार में बेचा जाता है। फिर शेष को अपीलकर्ता के फेरो मैंगनीज प्लांट (एफएमपी) में कच्चे माल के रूप में भेजा जाता है।

सी. तीसरा राज्य: फेरो मैंगनीज प्लांट में, कच्चे माल जैसे, संसाधित मैंगनीज अयस्क (जिसके लिए आईएमबी प्लांट द्वारा 40% बिजली शुल्क पहले से ही भुगतान किया जाता है), लौह अयस्क, कोक, डोलोमाइट, कोयला, कार्बन, आदि, के माध्यम से होते हैं। भट्टी के माध्यम से विनिर्माण प्रक्रिया, एक पूरी तरह से नए उत्पाद में मिश्रित होती है जिसे व्यावसायिक रूप से जाना जाता है और बाजार में फेरोमैंगनीज मिश्र धातु के रूप में बेचा जाता है जो कि अलग-अलग रसायन शास्त्र के साथ एक अलग उत्पाद है और भट्टी में गलाने के माध्यम से होता है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक विनिर्माण गतिविधि है, जहां मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, कोक, डोलोमाइट, कोयला, कार्बन आदि जैसे कच्चे माल पूरी तरह से उपभोग/समाप्त हो जाते हैं।

24. अपीलार्थी के फेरो मेंगनीज प्लांट को खान के अर्थ के भीतर लाना, राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि फेरो मेंगनीज संयंत्र का उपयोग खनिज, यानी मेंगनीज अयस्क को "कुचलने, प्रसंस्करण, उपचार या परिवहन के लिए" किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता न तो मेंगनीज अयस्क को कुचल रहा है, न प्रसंस्करण कर रहा है, न उपचार कर रहा है और न ही परिवहन कर रहा है, बल्कि इसे कच्चे माल में से एक के रूप में उपयोग कर रहा है और फेरोमेंगनीज मिश्र धातु के निर्माण के दौरान इसका उपभोग कर रहा है। मेंगनीज अयस्क (खनिज) को कुचलने, उपचारित करने, प्रसंस्करण आदि की स्थिति आईएमबी प्लांट (द्वितीय चरण) में थी, जहां अपीलकर्ता 40% बिजली शुल्क का भुगतान कर रहा है। वही दर फेरो मेंगनीज प्लांट (तीसरे चरण) में लागू नहीं की जा सकती क्योंकि उपरोक्त कारण से इसे "खान" के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है।

25. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क होगा कि कई निर्णयों में, इस न्यायालय ने दोहराया है कि यदि कोई नया पदार्थ अस्तित्व में लाया जाता है या यदि विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला कोई नया या अलग लेख विशेष प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, तो ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का निर्माण होगा। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता के मामले में, इस न्यायालय ने कहा: -

"11. सीमा शुल्क अधिनियम में "निर्माण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संबद्ध अधिनियम, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में भी, "निर्माण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि धारा 2 के खंड में एक समावेशी परिभाषा "निर्माण" शब्द इसलिए दिया गया है ताकि उसमें कुछ प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जा सके।

12. उजागर प्रिंट्स बनाम भारत संघ (1989) 3 एससीसी 488 मामले में "विनिर्माण" संविधान पीठ के विचार के लिए आया था। यह माना गया था कि यदि एक विशिष्ट चरित्र और उपयोग के साथ एक नया लेख अस्तित्व में आना चाहिए, जैसा कि प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप, माल के निर्माण को उचित ठहराने वाली आवश्यक शर्त पूरी हो जाती है। शब्दों और वाक्यांशों के स्थायी संस्करण में निम्नलिखित अंश को दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, एआईआर 1963 एससी 791 पृष्ठ 795 पर अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था:

"विनिर्माण" का तात्पर्य परिवर्तन से है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन निर्माण नहीं है और फिर भी किसी वस्तु का प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और हेरफेर का परिणाम है। लेकिन कुछ और आवश्यक है और परिवर्तन होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला एक नया और अलग लेख सामने आना चाहिए।

13. निर्णयों की एक श्रृंखला में [बुद्धि के लिए, डेकोरेटिव लैमिनेट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई, (1996) 10 एससीसी 46, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पारले प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड 1994 पूरक (3) एससीसी 662, लैमिनेटेड पैकिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई, (1990) 4 एससीसी 51 और एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, (1985) 3 एससीसी 314] इस न्यायालय द्वारा लगातार लिया गया दृष्टिकोण यह है कि इस समय एक नई वस्तु में परिवर्तन है जिसे व्यावसायिक रूप से एक विशिष्ट और अलग वस्तु के रूप में जाना जाता है, जिसका अपना चरित्र, उपयोग और नाम होता है, चाहे वह एक प्रक्रिया का परिणाम हो या कई प्रक्रियाओं का, निर्माण होता है; वस्तु का एक नई एवं भिन्न वस्तु में परिवर्तन इस प्रकार होना चाहिए कि व्यापारिक जगत में उसे दूसरी एवं भिन्न वस्तु के रूप में जाना जाए। पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो कैसेट निश्चित

रूप से बाजार में खाली ऑडियो कैसेट से अलग और अलग माने जाने वाले उत्पाद हैं। दोनों के अलग-अलग उपयोग हैं। पहले से रिकॉर्ड किया गया ऑडियो कैसेट आम तौर पर उसके नाम या शीर्षक के संदर्भ में बेचा जाता है जो कैसेट पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की सामग्री का संकेत देता है। अपीलकर्ता ऐसे पूर्व-रिकॉर्ड किए गए ऑडियो कैसेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन में लिप्त है। यह एक विनिर्माण गतिविधि है। अपीलकर्ता की गतिविधि की तुलना बाजार में बैठे किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है जो ग्राहक द्वारा लाए गए या उपलब्ध कराए गए खाली ऑडियो कैसेट पर किसी भी मांग वाले संगीत या ध्वनि को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे गतिविधि कहा जा सकता है। न्यायाधिकरण अपीलकर्ता की गतिविधि को फोटोप्रोसेसिंग के साथ जोड़कर और अपीलकर्ता को एक सेवा उद्योग मानकर सही नहीं था।"

26. एस्पिनवॉल एंड कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया है: -

"13. अधिनियम में "निर्माण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। "निर्माण" शब्द की परिभाषा के अभाव में इसका एक अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है। इसका अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि कच्चे या तैयार माल से उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन, ऐसी सामग्रियों को नए रूप, गुण या संयोजन देकर, चाहे हाथ से या मशीन श्रम द्वारा। यदि लेख में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक नया और अलग लेख आता है तो यह एक विनिर्माण गतिविधि होगी।

14. यह न्यायालय यह निर्धारित करते समय कि सीएसटीवी बनाम पियो फूड पैकर्स, 1980 पूरक एससीसी 174 में अभिनिर्धारित एक विनिर्माण गतिविधि की राशि क्या होगी : यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण, कि क्या निर्माण हुआ है,

यह कहा जा सकता है कि क्या वह वस्तु जो निर्माण की प्रक्रिया के अधीन है, उसे अब मूल वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन व्यापार में उसे एक नई और विशिष्ट वस्तु के रूप में मान्यता दी जाती है। यह देखा गया: (एससीसी पृष्ठ 176, पैरा 5)

"आम तौर पर निर्माण एक या अधिक प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम होता है जिसके माध्यम से मूल वस्तु को पारित किया जाता है। प्रसंस्करण की प्रकृति और सीमा एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न हो सकती है, और वास्तव में प्रसंस्करण के कई चरण हो सकते हैं और शायद प्रत्येक चरण में प्रसंस्करण का एक अलग प्रकार का हो सकता है। प्रत्येक प्रक्रिया के साथ, मूल वस्तु में परिवर्तन का अनुभव होता है। लेकिन यह तभी होता है जब परिवर्तन, या परिवर्तनों की एक श्रृंखला, वस्तु को उस बिंदु तक ले जाती है जहां व्यावसायिक रूप से इसे मूल वस्तु नहीं माना जा सकता है बल्कि इसे एक नए और विशिष्ट लेख के रूप में मान्यता दी गई है जिसके निर्माण के बारे में कहा जा सकता है।"

15. वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती कच्ची कॉफी बेरी को तोड़ने या प्राप्त करने के बाद इसे कॉफी बीन्स का आकार देने के लिए नौ प्रक्रियाओं से गुजरता है। शुद्ध उत्पाद इनपुट से बिल्कुल अलग और अलग है। वस्तु में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक नई और अलग वस्तु बनती है जिसे व्यापार में एक नई और विशिष्ट वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। कॉफी बीन्स की उस कच्चे माल से अलग एक स्वतंत्र पहचान होती है जिससे इसे बनाया जाता है। तैयार उत्पाद में एक अलग बदलाव आता है।

16. राजस्व के विद्वान वकील की यह दलील कि निर्धारिती केवल प्रसंस्करण कार्य कर रहा था और किसी नई वस्तु के निर्माण और उत्पादन में शामिल नहीं था,

स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया एक विनिर्माण प्रक्रिया है जब यह मूल वस्तु में पूर्ण परिवर्तन लाती है ताकि व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु या वस्तु का उत्पादन करे। उस प्रक्रिया में स्वयं कई प्रक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं। विभिन्न प्रक्रियाएँ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु का उत्पादन होता है। यदि कोई व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु या वस्तु प्रसंस्करण के बाद परिणाम देती है तो यह एक विनिर्माण गतिविधि होगी। करदाता कच्चे जामुन को संसाधित करने के बाद उन्हें कॉफी बीन्स में परिवर्तित करता है जो व्यावसायिक रूप से एक अलग वस्तु है। कच्ची बेरी को कॉफी बीन्स में बदलना एक विनिर्माण गतिविधि होगी।"

27. यह न्यायालय सर्वो-मेड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"27.(1) जहां किसी विशेष प्रक्रिया के बाद भी सामान बिल्कुल वैसा ही रहता है, वहां स्पष्ट रूप से कोई निर्माण शामिल नहीं होता है। ऐसी प्रक्रियाएं जो अपने आप में पूर्ण माल से विदेशी पदार्थ को हटा देती हैं और/या ऐसी प्रक्रियाएं जो अपने आप में पूर्ण हैं इस श्रेणी में आते हैं माल को साफ करती हैं।"

"27.(4) जहां सामान एक विशेष प्रक्रिया के बाद अलग और/या नए सामान में बदल जाता है, ऐसे सामान विपणन योग्य होते हैं। यह इस श्रेणी में है कि सामान का निर्माण होता है।"

28. इस प्रकार, फेरो मेंगनीज संयंत्र, मेंगनीज अयस्क को कुचलने, उपचार करने, प्रसंस्करण आदि में शामिल इकाई के विपरीत फेरो मेंगनीज मिश्र धातु के निर्माण में शामिल एक इकाई होने के नाते, इसे 'खदान' की विस्तारित परिभाषा अधिनियम की धारा

3(1) के लिए शुल्क की दरों की तालिका के भाग बी का स्पष्टीकरण (बी) के भीतर नहीं माना जा सकता है।

29. कार्यपालन अभियंता एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्य प्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 06.02.2005 द्वारा अधीक्षण अभियंता एवं उप विद्युत निरीक्षक, मध्य प्रदेश शासन को निम्नानुसार पुष्टि की थी:-

"मौके पर निरीक्षण से यह पुष्टि हुई है कि, फेरो मँगनीज प्लांट खनन क्षेत्र में नहीं आता है और वर्तमान में म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लिया जा रहा 8% विद्युत शुल्क उचित है।"

30. अपीलकर्ता द्वारा अपने फेरोमँगनीज संयंत्र में खनिज मँगनीज का उपयोग करके निर्मित फेरोमँगनीज मिश्र धातु भौतिक और यहां तक कि रासायनिक रूप से खनिज कच्चे माल से पूरी तरह से अलग उत्पाद है। इसके अलावा, मँगनीज अयस्क के विपरीत फेरोमँगनीज मिश्र धातु कभी भी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाई जा सकती है और इसे केवल मँगनीज अयस्क और अन्य खनिजों से ही निर्मित करना पड़ता है। यही तर्क तांबे के सांद्रण पर भी लागू होता है क्योंकि एक अलग और विशिष्ट उत्पाद अस्तित्व में आता है।

31. इस प्रकार विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि दोनों मामलों में, व्यावसायिक भाषा में अलग-अलग उत्पाद सामने आए हैं। इसलिए, हम यह सोचने के इच्छुक हैं कि नोसितुर ए सोसाईज़ के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। तार्किक परिणाम के रूप में, विनिर्माण इकाई के लिए टैरिफ लगाया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण सही नहीं है और तदनुसार, उसके द्वारा दिए गए निर्णय रद्द किए जाने योग्य हैं और हम ऐसा निर्देश देते हैं। हालाँकि, इस अवधि के दौरान यदि

अपीलकर्ताओं द्वारा राजस्व में कोई राशि का भुगतान किया गया है, तो उसे भविष्य की मांगों के लिए समायोजित किया जाएगा।

32. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये

इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।